

भाजपा सरकार उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी?

इस संभावना से आतंकित जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया और जब भाजपा हाईकमान त्याग पर कार्यवाही नहीं कर रहा था तो धनखड़ ने इस्तीफे की खबर अपने ट्विटर हैंडल पर डाली

-रेणु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 जुलाई। क्या मोदी सरकार बिखर रही है? क्या नेताओं का असंतोष मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहचान बनता जा रहा है, क्योंकि वे हर घटनाक्रम के कथानक पर नियन्त्रण करने की कोशिश तथा सिर्फ अपनी बात मनवाने और “यस सर” कहने वाली संस्कृति को सुनिश्चत कर रहे हैं?

जगदीप धनखड़ का इस्तीफ़ा और उससे जुड़े तमाम विवादों से यह साफ़ दिखता है कि मोदी सरकार किसी भी असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरकार का स्पष्ट और सीधा संदेश है – इस सरकार में सिर्फ़ हाँ में हाँ मिलाने वालों के लिए ही जगह है।

चाहे उपराष्ट्रपति से इस्तीफ़ा मांगा गया हो या उन्होंने खुद संकेत समझकर इस्तीफ़ा दिया हो, लेकिन दोनों ही स्थितियों का नतीजा एक ही है – प्रधानमंत्री और उनकी टीम की साख़ को बड़ा झटका लगा है।

खबर है कि सरकार उपराष्ट्रपति और

■ वैसे भी धनखड़ आरएसएस के नज़दीक माने जाते हैं तथा संघ के दबाव में ही धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया था और उसके पहले पश्चिम बंगाल का राज्यपाल।

■ कहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत व प्र.मंत्री नरेंद्र मोदी के तनाव की स्थिति की भी कुछ छाया तो नहीं है, धनखड़ प्रकरण पर।

■ इसके अलावा, हाल ही में अपनी कोटा यात्रा के दौरान, धनखड़ ने काफी तीखी आलोचना की थी, कोटा की कोचिंग क्लाॅसेज़ की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इस पर भारी आपत्ति की थी, क्योंकि अधिकतर कोचिंग इन्स्टीट्यूट के संस्थापक व संचालक ओम बिड़ला के नज़दीक के लोग बताये जाते हैं। ओम बिड़ला ने अपनी भावनाओं से गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया था और एक बार फिर जगदीप धनखड़ की पेशी हुई अमित शाह के सामने।

■ कई सवाल अनुत्तरित हैं, इस प्रकरण में, जिनका जवाब आना अभी बाकी है।

राज्यसभा के सभापति के खिलाफ़ रही थी।

अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर दोपहर बाद प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ

मंत्रियों के साथ बैठक की और फैसला किया कि अब कार्रवाई का समय आ गया है। राजनाथ सिंह से भाजपा सांसदों को फोन करके प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाने को कहा गया। कुछ मनोनीत सांसदों को भी बुलाया गया और सभी से इस बात को गोपनीय रखने को कहा गया।

धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के महाभियोग पर विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, जबकि सरकार चाहती थी कि भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर पहल वही करे। बताया गया है कि उन्होंने इस बारे में नेतृत्व को सूचित नहीं किया।

उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बहस की भी अनुमति दे दी, जिससे विपक्ष को विभिन्न प्रकार के सवाल पूछने का मौका मिलाता, जिनका सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता।

यह वही मुद्दा था, जिससे मोदी सरकार बचना चाहती थी, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद, पाकिस्तान के साथ सीमित बातचीत ही हुई थी।

धनखड़ को लगने लगा था कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान हाई कोर्ट में 7 नये न्यायाधीशों की अधिसूचना जारी

जयपुर, 22 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट को सात नए न्यायाधीश और मिल गए हैं, जिसके बाद अब हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। सात नए न्यायाधीशों में से छह अधिवक्ता कोटे से और एक न्यायिक अधिकारी कोटे से जज बने हैं। वकील

■ आशा की जा रही है कि राजस्थान हाई कोर्ट के काम की रफ्तार में तेजी आयेगी। अभी हाई कोर्ट में करीब 6 लाख साठ हजार मुकदमे लम्बित हैं।

कोटे से जज बनने वाले संदीप तनेजा, बलजिंदर सिंह, बिपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित, रवि चित्रानिया और अनुरूप सिंघी हैं, जबकि न्यायिक अधिकारी कोटे से संगीता शर्मा को हाईकोर्ट जज नियुक्त किया गया है। विधि एवं न्याय विभाग ने इस संबंध में नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। संदीप तनेजा को हाईकोर्ट का स्थाई जज और शेष छह को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मिग-21 की भारतीय वायु सेना से विदाई होगी

नई दिल्ली, 22 जुलाई। भारतीय वायु सेना रूस निर्मित मिग–21 लड़ाकू विमानों को संतबर में सेवानिवृत्त कर देगी। करीब 62 साल तक भारतीय वायुसेना को सेवा देने के बाद मिग–21 को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक खास समारोह में विदाई दी जाएगी।

मिग–21 को 1963 में वायु सेना में शामिल किया गया था। इस विमान ने 1965, 1971, 1999 और 2019 की सभी बड़ी सैन्य कार्रवाइयों में भाग लिया है। मिग–21 एक हल्का सिंगल पायलट फ़ाइटर ज़ेट है। सोवियत रूस के मिकोयान-गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने इसे

■ सूत्रों ने बताया कि 62 साल वायु सेना में सक्रिय रहे इन विमानों को चंडीगढ़ एयर बेस पर एक समारोह में विदाई दी जाएगी।

1959 में बनाना शुरू किया था। यह विमान 18 हजार मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ये एअर टू एअर मिसाइलों और बम को अपने साथ ले जाने में सक्षम है।

इसकी स्पीड अधिकतम 2,230 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1,204 नॉट्स (माक 2.05) तक की हो सकती है। 1965 और 1971 में हुए भारत-पाक युद्ध में मिग-21 विमानों का इस्तेमाल हुआ था। 1971 में भारतीय मिग ने चेंगडू एफ़ विमान (ये भी मिग का ही एक और वेरियंट था जिसे चीन ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकारों को नोटिस भेजा

मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आए ‘‘प्रेसिडेंशियल रैफ़रेंस’’ पर यह नोटिस भेजा गया है

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केन्द्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक प्रैसिडेंशियल रैफ़रेंस (राष्ट्रपति संदर्भ) पर जारी किया गया है, जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या अदालतें राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकती हैं।

नोटिस जारी करते हुए, मुख्य न्यायाधीश जी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंडुरकर की पांच-न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार, 29 जुलाई को सूचीबद्ध की है। कोर्ट ने एटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से मामले में सहायता करने का अनुरोध भी किया है।

8 अप्रैल, 2025 के ऐतिहासिक निर्णय में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला

क्या जगदीप धनखड़ प्रकरण ‘‘मैच फिक्सिंग’’ का मामला है?

अंततोगत्वा कांग्रेस अध्यक्ष को धनखड़ प्रकरण पर कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 जुलाई। जगदीप धनखड़ के इस्तीफ़े ने कांग्रेस पार्टी को भीतर से झकझोर दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ़ कहा है कि धनखड़ जाएं या रहें, यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है। इस मुद्दे का इस्तेमाल देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के उन नेताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश दिया है जो पूर्व उपराष्ट्रपति की खुलकर तारीफ़ कर रहे हैं और उनका बचाव कर रहे हैं।

इनमें सबसे प्रमुख हैं एआईसीसी मीडिया प्रभारी महासचिव जयराम रमेश, जो बार-बार पार्टी को असहज स्थिति में डाल चुके हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी ने उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है।

जयराम रमेश ने एक ट्वीट में लिखा:

“धनखड़ जी ने किसानों के हितों के लिए खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बढ़ते अहंकार की आलोचना की और न्यायपालिका की

■ एआईसीसी मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने, जगदीप धनखड़, जो कि कुछ दिन पूर्व तक कांग्रेस के शत्रु नंबर एक थे, की खुली तारीफ़ करके बड़ी अटपटी स्थिति पैदा की थी।

■ कई नेताओं व सांसदों ने खड़गे से मिलकर जयराम की इस प्रशंसा के खिलाफ़ शिकायत की।

■ गत दिसम्बर माह में कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनाई थी, पर, प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, क्योंकि, जयराम रमेश पहले अपना ही नाम गलत लिख दिया था तथा अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन का नोटिस देने की अनिवार्य औपचारिकता भी पूरी नहीं की थी, क्या यह ‘‘मैच फिक्सिंग’’ का मामला नहीं था।

■ परन्तु, अब स्वयं भाजपा सरकार धनखड़ को कठघरे में खड़ा कर देना चाहती है। अतः कथानक एक बार फिर गहरा रहा है।

जवाबदेही व संयम की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने जहां तक संभव हो सका, विपक्ष को जगह देने की कोशिश की।

वह नियमों, प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के पक्के थे...”

धनखड़, जिन्हें कुछ समय पहले

तक कांग्रेस का दुश्मन नंबर एक माना

जा रहा था, उनकी इतनी प्रशंसा से पार्टी

में कई लोगों की भीड़ तन गई हैं। कई नेताओं और सांसदों ने खड़गे से इस पर नाराजगी जताई, जिसके बाद खड़गे ने सार्वजनिक रूप से पार्टी की स्थिति साफ़ कर दी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या वरिष्ठ जेडीयू नेता हरिवंश सिंह बन सकते हैं नए उपराष्ट्रपति?

वर्तमान में वे राज्यसभा के उपसभापति हैं और सभी दलों से उनका अच्छा तालमेल बताया जाता है

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 जुलाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफ़े ने सत्तारूढ़ भाजपा में हलचल मचा दी है, इसने प्रधानमंत्री के खेमे और आरएसएस के बीच गहरी फूट को उजागर कर दिया है। इस्तीफ़े का आधिकारिक कारण भले रही स्पष्ट नहीं हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि धनखड़ का कार्य करने का तरीका लंबे समय से वरिष्ठ भाजपा नेताओं और आरएसएस के भीतर के लोगों को नाखुश करता आ रहा था।

कई महीनों से सूत्र ये संकेत दे रहे थे कि धनखड़ के राज्यसभा के सभापति के रूप में बढ़ते हुये अडिगल रवैये और हस्तक्षेपों से न केवल विपक्षी दलों को, बल्कि एनडीए के कुछ सहयोगियों को भी असुविधा हो रही थी।

संघ परिवार के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, धनखड़, जो राजस्थान के झुंझुनूं से हैं और एक वकील से राजनेता बने हैं, अब भाजपा के शीर्ष नेताओं या

■ समझा जाता है कि सरकार गठबंधन की मजबूती का संकेत देने और सहयोगियों को खुश करने के लिए यह कदम उठा सकती है।

■ इसी क्रम में तेलुगू देशम पार्टी के किसी नेता को उपसभापति बनाने की भी चर्चा है, इसे चंद्रबाबू नायडू को राजी करने की कोशिश बताया जा रहा है, जो कुछ समय से कई मसलों पर भाजपा से अलग राय व्यक्त कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री के करीबी हलकों में एक असेट (मूल्यावान व्यक्ति) के रूप में नहीं देखे जा रहे थे।

महत्वपूर्ण बात यह है कि धनखड़ के कार्यकाल में अभी दो साल शेष थे। इसलिये उनका इस्तीफा केवल एक सामान्य राजनीतिक फेरबदल से कहीं अधिक प्रतीत होता है, यह गंभीर आंतरिक पुनः संतुलन का एक संकेत है। एक वरिष्ठ आरएसएस कार्यकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि धनखड़ की “अपनी उपयोगिता पूरी हो गई थी” और अब वे मोदी-शाह नेतृत्व की बदलती

राजनीतिक रणनीति से मेल नहीं खा रहे थे। लेकिन उन्हें हटाने का निर्णय लेना आसान नहीं था। इसके लिए कई शक्ति केन्द्रों में सहमति की आवश्यकता थी, जैसे भाजपा नेतृत्व, संघ और एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल।

इसी बीच, अब यह खबरें आ रही हैं कि एनडीए संसद में एक बड़े पुनर्गठन पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति और वरिष्ठ जेडी (यू) नेता हरिवंश सिंह को धनखड़ के स्थान पर लाने के विकल्प (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ब्रिटिश नौसेना का लड़ाकू विमान मरम्मत के बाद वापस गया

तिरुवनंतपुरम (केरल), 22 जुलाई। ब्रिटिश नौसेना का लड़ाकू विमान एफ–35 आखि़कार ब्रिटेन के लिए रवाना हो गया है। लगभग एक महीने से भारत में खड़े रहे इस विमान ने आज तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से उड़ान भरी है।

■ एफ-35 फ़ाइटर जेट का हाइड्रॉलिक सिस्टम खराब हो गया था तथा उसे तिरुवनंतपुरम में आपात लैंडिंग करने पड़ी थी। ब्रिटिश इंजीनियरों को इसे ठीक करने में 38 दिन लगे।

ब्रिटिश नेवी का यह एअरक्राफ्ट एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स का हिस्सा है। इसने 14 जून को केरल के तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। विमान में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-अंजन राॅय-

-अमेरिका में राष्ट्रदूत के प्रतिनिधि-वॉशिंग्टन, 22 जुलाई। अगले साल होने वाले मध्यावधि चुनावों से कुछ ही महीने पहले, अमेरिका में मतदाता ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर पहले की तरह ही विभाजित नज़र आ रहे हैं, चाहे वह निम्हा हो, या उनके कार्यकाल का मूल्यांकन।

डॉनल्ड ट्रंप के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए दो मुद्दे विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनकर उभरे हैं। पहला है महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत का मुद्दा, जहाँ ट्रंप के वफादार समर्थक भी बढ़ती कीमतों की मार महसूस कर रहे हैं।

लोगों को, चाहे उनका राजनीतिक रङ्गान कुछ भी हो, लगता है कि कीमतें लगातार ऊँची बनी हुई हैं और इससे आम अमेरिकी का जीवन प्रभावित हो

रहा है। पिछले राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप ने महंगाई के मुद्दे को बड़े प्रभावी ढंग से उठाया था।

यहाँ संदर्भ समझना जरूरी है। बाइडन प्रशासन के शुरुआती दिनों में बहुत अधिक महंगाई देखी गई थी, जिसे बाद में काबू में लाया गया। लेकिन बदनामी तो हो चुकी थी। ट्रंप ने बार-बार इसे बाइडन की विफलता के रूप में दर्शाया और वादा किया कि वे कीमतों और जीवन-यापन को बेहतर बनाएंगे। लेकिन बड़े हुए दामों ने परिवारों के बजट को लगातार प्रभावित किया और अभी भी यह एक बड़ी चिंता बनी हुई है।

तथापि, कुछ मतदाता मानते हैं कि नौकरी की संभावनाएँ और समग्र स्थिरता अब बेहतर हो रही है, भले ही जीवन की लागत अधिक हो। दूसरा मुद्दा है, एक सैक्स रैंकेट स्कैंडल, जो मृत उच्च-प्रोफाइल

■ सब मानते हैं, महंगाई बढ़ी है, पर, ट्रंप के वफादार फिर भी यह मानते हैं कि बड़ी हुई महंगाई के बावजूद देश में शांति व ‘‘स्टेबिलिटी’’ (स्थिरता) है।

■ दूसरा प्रमुख मुद्दा, ट्रंप प्रशासन के मूल्यांकन के बारे में है, उनकी (ट्रंप की) बाल यौनाचार के आरोपी ‘‘एपस्टीन’’ से नज़दीकी के बारे में। ट्रंप के पुराने वफादार व समर्थक अभी भी ट्रंप को निर्दोष मानते हैं, पर, कुछ कट्टर समर्थक भी अब यह मानने लगे हैं कि ट्रंप को खुलकर अपना पक्ष जनता के सामने रखना चाहिए, क्योंकि, अब वह मोड़ आ गया है, जबकि जनता ‘‘सत्य व पूर्ण सत्य को जाने बगैर संतुष्ट नहीं होगी।’’

सामाजिक हस्ती एपस्टीन से जुड़ा है। एपस्टीन के साथ नजदीकियों ने अमेरिका और इंग्लैंड के कई शीर्ष लोगों को संकट में डाल दिया, जिनमें किंग चार्ल्स के छोटे भाई भी शामिल हैं।

एपस्टीन पर सबसे गंभीर आरोप ये हैं कि उसने मशहूर हस्तियों के लिए ‘‘चाइल्ड सैक्स’’ का आयोजन किया। उदाहरण के लिए, प्रिंस एंड्रयू पर ऐसे ही आचरण का आरोप लगा था, जिसकी

वजह से उन्हें शाही जिम्मेदारियों से कुछ समय के लिए दूर रखा गया।

डॉनल्ड ट्रंप पर एपस्टीन के करीबी होने के आरोप लगे हैं और अब यह आरोप भी लगा रहा है कि वे उसके नजदीकी सर्कल का हिस्सा थे। ट्रंप ने स्वाभाविक रूप से सभी आरोपों का खंडन किया है, लेकिन उनकी सफाइयों अक्सर अस्पष्ट और भ्रमित करने वाली बताई जा रही हैं। अपने संबंधों से इन्कार करते समय वो कुछ हिचकिचाए हैं।

हालाँकि, अब मतदाता यह चाहते हैं कि राष्ट्रपति पूरी सच्चाई सामने रखें। यहाँ तक कि उनके वफादार समर्थक और रिपब्लिकन भी मांग कर रहे हैं कि सभी दस्तावेज जनता के सामने पेश किए जाएँ, ताकि सच्चाई सामने आ सके, क्योंकि ‘‘सिर्फ सच्चाई ही संतुष्टि दे सकती है।’’

प्रमुख समाचार एजेंसी सी.एन.एन.

ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का मूल्यांकन किया। एजेंसी ने अपने उस डेटा बेस का इस्तेमाल किया, जिसमें वो लोग शामिल थे, जिन्हें एजेंसी कई वर्षों से फॉलो कर रही थी। न्यूज़ चैनल ने उन लोगों को टैक किया, जिन्होंने पिछले राष्ट्रपति चुनाव से पहले उसके सर्वेक्षण में हिस्सा लिया था और अब एक बार फिर उनसे संपर्क करके उनसे उनका मूल्यांकन लिया गया है। हालाँकि कई समर्पित ट्रंप समर्थकों ने अपना समर्थन कायम रखा है, लेकिन कुछ कट्टर समर्थकों ने भी अब यह मांग की है कि राष्ट्रपति और प्रशासन को ट्रंप की नैतिकता से जुड़ी बातों को लेकर पारदर्शिता दिखानी चाहिए।

कुछ वफादार तो यह विश्वास भी नहीं कर रहे हैं कि राष्ट्रपति सच्चाई बता रहे हैं, या उनके जवाब उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट कर पा रहे हैं कि असली मुद्दा क्या था।

चाहिए। इस निर्णय की अन्य मुख्य बातें थीं कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत पॉकेट वीटो (राज्यपाल द्वारा बिना निर्णय (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुम्बई ट्रेन धमाकों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

नयी दिल्ली, 22 जुलाई। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के 2006 के ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 दोषियों को

■ महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई ट्रेन धमाकों में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बाम्बे हाईकोर्ट ने इस आतंकी घटना के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस घटना में 189 लोग मरे थे व 820 गंभीर घायल हुए थे।

बरी करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

नियम के बिना और अभिमान के साथ किया गया तप व्यर्थ ही होता है। –वेदव्यास

जांच और अभियोजन की खामियां दर्शाता अदालती फैसला

मुंबई में 11 जुलाई, 2006 को विभिन्न स्थानों पर लोकल ट्रेनों में सात विस्फोट हुए, जिनमें 180 से ज़्यादा लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए थे। इसके उन्नीस साल बाद, बाँम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को उनके सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा और “यह विश्वास करना मुश्किल है कि उन्होंने अपराध किया है”। यह फैसला अपराध की जांच करने वाली एजेंसी और अभियोजन पक्ष के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी लेकर आया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हाल के वर्षों में अनेकों ऐसे फैसले आए हैं जिनमें बरसों से जेलों में बंद लोग बरी किए गये हैं। हालांकि ऐसे फैसले भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं विश्वसनीयता को स्थापित करते हैं किन्तु वे न्याय प्रक्रिया में देरी की ओर भी ध्यान खींचते हैं। साथ ही वे जांच एजेंसियों और अभियोजन पक्ष की खामियों व कमजोरियों को भी उजागर करते हैं। वर्षों तक मुकदमा चलने के बाद अभियुक्तों की रिहाई भारतीय न्यायिक तंत्र की गंभीर और बहुआयामी समस्या के साथ सामाजिक, आर्थिक और मानवीय पीड़ा को भी दर्शाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन जब एक व्यक्ति बरसों तक अदालतों में घसीटा जाता है और अंततः उच्च न्यायालय उसे बरी कर देता है, तब यह प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है कि क्या वह केवल एक न्यायिक निर्णय है या वर्षों की पीड़ा और अन्याय की स्वीकृति है। अधिकतर मामलों में ट्रायल कोर्ट में दोष सिद्ध हो जाते हैं, परंतु ऊपर के न्यायालयों में अपील के दौरान यह स्पष्ट होता है कि साक्ष्य अपर्याप्त थे या गवाहों की गवाही टिकने वाली नहीं थी। इससे ट्रायल अदालतों के निर्णयों पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं। इस बार भी हुआ है जिसमें न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ ने मुंबई हादसों के बारे में कहा कि अभियोजन पक्ष अपराध में इस्तेमाल किए गए बमों के प्रकार को भी रिकॉर्ड में दर्ज करने में विफल रहा है और जिन सबूतों पर उसने भरोसा किया है, वे आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए निर्णायक नहीं हैं। हाईकोर्ट ने 12 लोगों की दोषसिद्धि को रद्द करते हुए कहा कि गवाहों के बयान और आरोपियों से की गई कथित बरामदगी का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है। इन 12 लोगों में से पांच को एक विशेष अदालत ने मौत की सजा और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने कहा, “अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है। इसलिए उनकी दोषसिद्धि रद्द की जाती है।” इस फैसले में अभियोजन पक्ष की कमजोरियों पर भी टिप्पणियां हैं कि वह मामले के महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ करने में विफल रहा तथा बरामद वस्तुओं का खराब और अनुचित रखरखाव करके प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला। पीठ ने कहा, “अभियोजन पक्ष कथित अपराध में इस्तेमाल किए गए बमों के प्रकार को भी रिकॉर्ड में दर्ज करने में विफल रहा है।” उच्च न्यायालय ने मामले के कुछ आरोपियों के कथित इकबालिया बयानों को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा लगता है कि ये बयान उन्हें यातना देकर लिए गए थे। पीठ ने कहा, “इकबालिया बयान अधूरे और असत्य पाए गए हैं क्योंकि कुछ हिस्से एक-दूसरे को नकल हैं। आरोपियों ने यह साबित कर दिया है कि उस समय उन्हें यातनाएं दी गई थीं।” अदालत ने आरोपियों की पहचान परेड को भी खारिज कर दिया और कहा कि संबंधित पुलिस को ऐसा करने का कोई अधिकार ही नहीं था। उच्च न्यायालय ने गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्यों को भी स्वीकार करने से यह कह कर इनकार कर दिया कि “गवाहों के बयान विश्वसनीय या भरोसेमंद नहीं हैं और आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए निर्णायक नहीं हैं। गवाहों ने घटना के चार महीने बाद पुलिस के सामने शिनाख्त परेड के दौरान और फिर चार साल बाद अदालत में आरोपियों की पहचान की।” इन गवाहों को घटना वाले दिन आरोपियों को देखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला था ताकि वे बाद में उनकी सही पहचान कर सकें। न्यायधीशों ने कहा कि हमें ऐसा कोई कारण नहीं मिला जिससे उनकी स्मृति जागृत हो और चेहरे याद आ सकें।”

अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में निर्दोष साबित होने पर सरकार द्वारा मुआवजा, पुनर्वास सहायता, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग तथा रोजगार पुनर्स्थापन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। भारत में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बरसों तक मुकदमे झेलने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रिहाई भले ही कानूनी दृष्टि से न्याय का प्रतीक हो, परंतु मानवीय दृष्टिकोण से यह एक त्रासदी ही कही जाएगी।

अभियुक्तों पर कैसा सामाजिक व मानसिक दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिन लोगों ने वर्षों जेल में बिताए, वे मानसिक रूप से टूट जाते हैं। उनकी पहचान समाज में ‘अपराधी’ के रूप में स्थापित हो जाती है, चाहे उन्हें बाद में निर्दोष घोषित कर दिया जाए। समाज में उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। रोजगार, शादी, और सामाजिक प्रतिष्ठा जैसी चीजें उनसे छिन जाती हैं। एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया मंद न केवल व्यक्ति की आय प्रभावित होती है, बल्कि उसके परिवार पर भी भारी आर्थिक बोझ पड़ता है – कहींलों की फीस, कोर्ट की तारीखों पर जाना, नौकरी छूट जाना आदि। हालांकि कहा यह जाता है कि बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेशन मगर भारत में जमानत के सिद्धांत को आमतौर पर पूरी तरह नज़रअंदाज किया जाता है। परिणामस्वरूप, आरोपी बिना दोष सिद्ध हुए सालों तक जेल में बंद रहता है। इसीलिए ऐसे में केवल दोषमुक्त ही नहीं, पुनर्वास और क्षतिपूर्ति को भी उतना ही अनिवार्य बनाए जाने की मांग होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि देश में सच्चे अर्थों में संवैधानिक और मानवीय न्याय की व्यवस्था करनी है, तो न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना होगा। सच तो यह है कि भारतीय न्याय व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी न्यायिक प्रणालियों में से एक है, परंतु यह समान रूप से धीमी और जटिल भी है। हमारे यहां ट्रायल कोर्ट की त्रुटियों पर भी यदा-कदा ऊपरी अदालतें नाराजगी जताते हुए टिप्पणियां करती हैं। बहुत बार निचली अदालतें साक्ष्यों की ठीक से व्याख्या नहीं कर पाती या अभियुक्तों के पक्ष को पर्याप्त सुनवाई का अवसर नहीं देतीं, जिससे उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के बाद अभियुक्त बरी कर दिए जाते हैं।

हालांकि मुकदमे लंबे खिंचते हैं, परंतु उच्च न्यायालय कई बार न्याय की अंतिम आशा बनकर सामने आते हैं। वे तथ्यों और साक्ष्यों की विस्तृत समीक्षा करते हैं और जांच तथा ट्रायल में हुई खामियों को उजागर करते हैं जैसा मुंबई की ट्रेनों में विस्फोटों के मुकदमे में हुआ है। उच्च न्यायालयों द्वारा दी गई रिहाई कई बार न्यायिक दखल और विवेक की मिसाल बनती है, लेकिन यह भी सत्य है कि उस निर्णय तक पहुंचने में जितनी देर हुई, वह आरोपी के जीवन की अपूरणीय क्षति बन जाती है। यहां यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है – क्या वर्षों बाद अदालत से बरी हो जाना न्याय है? लंबे समय तक जेल में रहना, कोर्ट की तारीखों का बोझ, अपनों से बिछड़ना – यह सब किसी को भी मानसिक रूप से तोड़ सकता है। कई मामलों में रिहा हुए लोगों को मानसिक रोगों से जूझते हुए भी पाया गया है। रिहाई के बाद जीवन को फिर से सामान्य पटरी पर लाना अत्यंत कठिन होता है। न तो समाज उसे सहज स्वीकार करता है, न ही उसका आत्मबल उसे फिर से जीवन में स्थापित होने देता है। इसलिए समाजशास्त्री व मनोवैज्ञानिक ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति की आवश्यकता प्रतिपादित करते हैं, ताकि बरी हुए लोगों का पुनर्वास हो सके और उन्हें समाज में पुनः स्थापित होने में सहयोग दिया जा सके। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में निर्दोष साबित होने पर सरकार द्वारा मुआवजा, पुनर्वास सहायता, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग तथा रोजगार पुनर्स्थापन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। भारत में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बरसों तक मुकदमे झेलने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रिहाई भले ही कानूनी दृष्टि से न्याय का प्रतीक हो, परंतु मानवीय दृष्टिकोण से यह एक त्रासदी ही कही जाएगी। यह स्थिति न केवल हमारी न्याय प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करती है, बल्कि बल्कि करुणा और उत्तरदायित्व की भावना से नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। यदि हमें सच्चे अर्थों में अदालतों को न्याय के मंदिर बनाना है, तो हमें ऐसी व्यवस्था बनाने की तरफ बढ़ना होगा जिसमें किसी निर्दोष को वर्षों जेल में नहीं रहना पड़े क्योंकि किसी को लंबे समय तक बंदी बनाए रखने के बाद रिहा कर देना, न्याय नहीं – न्यायतंत्र की गम्भीर विफलता है। इस दर्द को समझा जाना चाहिए और न्याय प्रक्रिया को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए जिससे हर वह व्यक्ति न्याय पा सके जो वर्षों से केवल एक तारीख की उम्मीद में जी रहा है।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

राशिफल

बुधवार 23 जुलाई, 2025

सावन मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, आर्द्रा नक्षत्र सायं 5:54 तक, व्यापार योग दिन 12:34 तक, विधि करण दिन 3:34 तक, चन्द्रमा आज मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-सिंह, बुध-कर्क, गुरु-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज भद्रा दिन 3:34 तक रहेगी। बुध अस्त पश्चिम में रात्रि 2:55 पर होगा। आज मास शिवरात्रि है। आज से राष्ट्रीय सावन मास आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:13 तक, शुभ 10:52 से 12:33 तक, चर 3:54 से 5:35 तक, लाभ 5:35 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:50, सूर्यास्त 7:16



मेघ

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों मदद-बंधुओं के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।



तुला

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटकें हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।



वृष

आर्थिक कारणों से अटकें हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।



वृश्चिक

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा शुभ नहीं है।



मिथुन

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों योजनानुसार बनने लगेंगे। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



धनु

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्यों सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कर्क

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। वाणी पर संयम रखें।



मकर

परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।



सिंह

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेंगी।



कुंभ

व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। कारोबारी अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।



कन्या

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटकें हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मीन

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आय में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



अशोक कुमार

राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई नई नीति, जिसके अंतर्गत राज्य के 335 राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्यों की नियुक्ति पांच वर्षों के अनुबंध पर की जाएगी, न केवल शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाली नीति है, बल्कि यह उच्च शिक्षा की मूल

आत्मा और के मूल उद्देश्यों के भी प्रतिकूल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देशभर में उच्च शिक्षकों के लिए जो वेतनमान निर्धारित किए हैं, वे सामान्य सेवाओं से कहीं अधिक हैं और इसके पीछे एक स्पष्ट सोच रही है – देश के श्रेष्ठतम मस्तिष्कों को शिक्षा और अनुसंधान की दिशा में प्रेरित करना। क्योंकि जब शिक्षक सामाजिक, आर्थिक और कार्यस्थल की दृष्टि से सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं, तभी वे शिक्षण, शोध और नवाचार में अपनी ऊर्जा और समर्पण दे सकते हैं।

राजस्थान की नई नीति में शिक्षकों को केवल 28,000 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया जाएगा, जो कि द्वारा निर्धारित 57,700 रुपये न्यूनतम वेतन के लगभग आधे से भी कम है। यह स्थिति न केवल शिक्षकों की गरिमा के विरुद्ध है, बल्कि इससे युवाओं में उच्च शिक्षा

को करियर विकल्प के रूप में चुनने की इच्छा भी क्षीण होगी। एक तरफ हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम शिक्षकों को अस्थायी संविदा पर अल्प वेतन में कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं, जो स्पष्ट रूप से दोहरी मानसिकता को दर्शाता है।

शिक्षा केवल नौकरी नहीं होती, वह समाज निर्माण का कार्य है। एक सहायक आचार्य जब कॉलेज में प्रवेश करता है, तो वह विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता, बल्कि उन्हें जीवन के उच्च मूल्यों, शोध की संस्कृति और नवाचार की दिशा में भी मार्गदर्शन देता है। यदि उसका स्वयं का भविष्य अनिश्चित हो, तो वह अपने छात्रों को स्थायित्व और लक्ष्य की प्रेरणा कैसे दे पाएगा?

विद्या संवल योजना के समाप्त करने और गुजरत मॉडल के आधार पर संविदा शिक्षक नियुक्त करने का निर्णय

यह दर्शाता है कि सरकार तात्कालिक वित्तीय प्रबंधन को दीर्घकालिक शिक्षा नीति पर वरीयता दे रही है। क्या शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जिनमें शिक्षकों की योग्यता, सुरक्षा और प्रेरणा के साथ समझौता हो?

राजकीय महाविद्यालय पहले ही शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। शोध, नवाचार और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार तभी संभव है जब योग्य शिक्षक स्थायित्व और सम्मान के साथ कार्य कर सकें। तीन वर्षों के अंतराल पर प्राचार्यों का कार्यकाल बढ़ाने की योजना भी केवल पद की निरंतरता को सुनिश्चित करती है, न कि संस्था की गुणवत्ता को। आवश्यक है कि पदस्थापन और सेवा विस्तार की कोई भी योजना केवल अनुभव नहीं बल्कि निष्पक्ष मूल्यांकन के आधार पर हो।

यह नीति केवल एक शॉर्टकट

राजस्थान में उच्च शिक्षा पर संकट : संविदा शिक्षकों की नई नीति और उसके गंभीर परिणाम



अशोक कुमार

राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई नई नीति, जिसके अंतर्गत राज्य के 335 राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्यों की नियुक्ति पांच वर्षों के अनुबंध पर की जाएगी, न केवल शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाली नीति है, बल्कि यह उच्च शिक्षा की मूल

आत्मा और के मूल उद्देश्यों के भी प्रतिकूल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देशभर में उच्च शिक्षकों के लिए जो वेतनमान निर्धारित किए हैं, वे सामान्य सेवाओं से कहीं अधिक हैं और इसके पीछे एक स्पष्ट सोच रही है – देश के श्रेष्ठतम मस्तिष्कों को शिक्षा और अनुसंधान की दिशा में प्रेरित करना। क्योंकि जब शिक्षक सामाजिक, आर्थिक और कार्यस्थल की दृष्टि से सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं, तभी वे शिक्षण, शोध और नवाचार में अपनी ऊर्जा और समर्पण दे सकते हैं।

राजस्थान की नई नीति में शिक्षकों को केवल 28,000 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया जाएगा, जो कि द्वारा निर्धारित 57,700 रुपये न्यूनतम वेतन के लगभग आधे से भी कम है। यह स्थिति न केवल शिक्षकों की गरिमा के विरुद्ध है, बल्कि इससे युवाओं में उच्च शिक्षा

को करियर विकल्प के रूप में चुनने की इच्छा भी क्षीण होगी। एक तरफ हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम शिक्षकों को अस्थायी संविदा पर अल्प वेतन में कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं, जो स्पष्ट रूप से दोहरी मानसिकता को दर्शाता है।

शिक्षा केवल नौकरी नहीं होती, वह समाज निर्माण का कार्य है। एक सहायक आचार्य जब कॉलेज में प्रवेश करता है, तो वह विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता, बल्कि उन्हें जीवन के उच्च मूल्यों, शोध की संस्कृति और नवाचार की दिशा में भी मार्गदर्शन देता है। यदि उसका स्वयं का भविष्य अनिश्चित हो, तो वह अपने छात्रों को स्थायित्व और लक्ष्य की प्रेरणा कैसे दे पाएगा?

विद्या संवल योजना के समाप्त करने और गुजरत मॉडल के आधार पर संविदा शिक्षक नियुक्त करने का निर्णय

यह दर्शाता है कि सरकार तात्कालिक वित्तीय प्रबंधन को दीर्घकालिक शिक्षा नीति पर वरीयता दे रही है। क्या शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जिनमें शिक्षकों की योग्यता, सुरक्षा और प्रेरणा के साथ समझौता हो?

राजकीय महाविद्यालय पहले ही शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। शोध, नवाचार और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार तभी संभव है जब योग्य शिक्षक स्थायित्व और सम्मान के साथ कार्य कर सकें। तीन वर्षों के अंतराल पर प्राचार्यों का कार्यकाल बढ़ाने की योजना भी केवल पद की निरंतरता को सुनिश्चित करती है, न कि संस्था की गुणवत्ता को। आवश्यक है कि पदस्थापन और सेवा विस्तार की कोई भी योजना केवल अनुभव नहीं बल्कि निष्पक्ष मूल्यांकन के आधार पर हो।

यह नीति केवल एक शॉर्टकट

समाधान है, जो दीर्घकालिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और स्थायी बनाना होगा। शिक्षकों को राष्ट्रीय वेतनमान, सेवा सुरक्षा और शोध के लिए सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। तभी हम एक ऐसा शिक्षण तंत्र विकसित कर सकते हैं जो भारत को वैश्विक ज्ञान-शक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर हो सके। शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए शिक्षक की पूर्णिका केंद्रीय है। यदि हम शिक्षा को भविष्य का निवेश मानते हैं, तो हमें शिक्षकों को केवल संविदा कर्मी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता के रूप में देखना होगा।

–अशोक कुमार,

पूर्व कुलपति कानपुर,

गौरखपुर विश्वविद्यालय,

विभागाध्यक्ष राजस्थान

विश्वविद्यालय जयपुर



कुणाल वशिष्ठ

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत राजस्थान ने स्वच्छता और शहरी प्रबंधन के क्षेत्र में देशभर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा 233 नगरीय निकायों में 3 हजार 799 करोड़ की योजनाओं की क्रियान्विति की जा रही है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शौचालय निर्माण, प्रयुक्त जल प्रबंधन, क्षमता संवर्धन और जन-जागरूकता जैसे विविध घटकों को शामिल किया गया है। राज्य में 219 करोड़ की लागत से अब तक 29961 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 8068 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे राजस्थान के लाखों नागरिकों को स्वच्छ वातावरण के साथ-साथ सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं।

प्रयुक्त जल प्रबंधन के अंतर्गत एक लाख से कम जनसंख्या वाले 208 नगरीय निकायों में 1 हजार 785 करोड़ की लागत से कार्य प्रस्तावित है, जिनमें से 41 शहरों में कार्य आवंटित कर दिए गए हैं। ठोस

अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत राज्य में 1372 करोड़ की लागत से 233 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, 7 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र तथा 152 लाख घन मीटर लेगेसी वेस्ट के निस्तारण का कार्य किया जा रहा है। इनमें से 153 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, 5 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र तथा 76 लाख घन मीटर लेगेसी वेस्ट का कार्य प्रगतिरत है, जबकि 2 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र तथा 76 लाख घन मीटर से अधिक लेगेसी वेस्ट निस्तारण का कार्य सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इसके साथ ही राज्य में 301 स्थाई मुख्यमंत्री भवनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा 233 नगरीय निकायों में 3 हजार 799 करोड़ की योजनाओं की क्रियान्विति की जा रही है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शौचालय निर्माण, प्रयुक्त जल प्रबंधन, क्षमता संवर्धन और जन-जागरूकता जैसे विविध घटकों को शामिल किया गया है। राज्य में 219 करोड़ की लागत से अब तक 29961 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 8068 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे राजस्थान के लाखों नागरिकों को स्वच्छ वातावरण के साथ-साथ सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं।

प्रयुक्त जल प्रबंधन के अंतर्गत एक लाख से कम जनसंख्या वाले 208 नगरीय निकायों में 1 हजार 785 करोड़ की लागत से कार्य प्रस्तावित है, जिनमें से 41 शहरों में कार्य आवंटित कर दिए गए हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत राज्य में 1372 करोड़ की लागत से 233 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, 7 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र तथा 152 लाख घन मीटर लेगेसी वेस्ट के निस्तारण का कार्य किया जा चुका है। इसके साथ ही राज्य में 301 स्थाई मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित कर नागरिक संवाद और जनसहभागिता को और अधिक मजबूत किया गया है।

कचरे से समृद्धि की ओर बढ़ता राजस्थान :-राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के बहुमुखी विकास के लिए नवाचार को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खरों के निर्देशन में सीकर नगर परिषद ने “शून्य अपशिष्ट, शून्य लागत” मॉडल के तहत प्रतिदिन 125 टन कचरे का निस्तारण कर स्थानीय किसानों को 2 प्रति किलोग्राम दर से उच्च गुणवत्ता की खाद उपलब्ध करवाई है। जोबनर और बस्सी नगर निकायों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ऑन-साइट प्रशिक्षण देकर ठोस कचरा प्रबंधन में जोड़ा गया है, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है। जयपुर के लांगडियावास स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में प्रतिदिन 1000 टन कचरे का निस्तारण कर उससे 12 मेगा वाट



विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, जो राज्य के सतत ऊर्जा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में राजस्थान की चमकदार उपलब्धि : स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ढूंगरपुर शहर को सुपर स्वच्छता लीग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि जयपुर नगर निगम ग्रेटर को प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर के रूप में पहचान मिली। राज्य के 12 शहर देश के प्रथम 100 स्वच्छ शहरों में शामिल हुए हैं और पहली बार तीन शहरों को वाटर प्लस श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि राज्य के सभी 240 शहरों की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में अप्रत्याशित सुधार दर्ज हुआ है।

स्थायी परिवर्तन की ओर :

स्वच्छ ऊर्जा और हरित नवाचार की नई राह, राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब एक लाख परिवारों को निःशुल्क इंडक्शन कुकटॉप मिलेंगे, जिससे न सिर्फ धुएँ से मुक्ति मिलेगी, बल्कि रसोई में ऊर्जा की नयी क्रांति भी आएगी। ग्रामीण इलाकों में प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर बढ़ते हुए ग्राम पंचायतों में ‘बर्तन बैंक’ की अनूठी पहल शुरू की जा रही है, जिससे सामाजिक आयोजनों में प्लास्टिक के स्थान पर पुनः उपयोग योग्य बर्तनों का प्रयोग हो सके। उल्लेखनीय है कि अब तक जयपुर सहित कुल 41 जिलों की 1000 ग्राम पंचायतों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ ही, वेस्ट टू वेयर पार्क और स्लीन एंड टीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर जैसे

नवाचारों से राज्य में पर्यावरण संरक्षण को तकनीकी आयाम मिल रहा है, यह सिर्फ एक पहल नहीं, बल्कि हरित विकास की ओर निर्णायक यात्रा है। ये अभूतपूर्व निर्णय और उपलब्धियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में न केवल बुनियादी सुविधाएँ सुदृढ़ की हैं, बल्कि नवाचार, सहभागिता और समावेशी विकास के माध्यम से एक स्थायी और स्वच्छ भविष्य की नींव रखी है। राजस्थान की यह यात्रा न केवल राज्य के लिए गौरव का विषय है, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणास्पद उदाहरण भी प्रस्तुत करती है।

कुणाल वशिष्ठ,

जनसंपर्क अधिकारी,

स्वायत्त शासन विभाग।

‘ अधिकारी पेंडिंग फाइलों का जल्द निस्तारण कर आमजन को दे राहत ’

आयुक्त ने निगम अधिकारियों को सड़कस्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य के लिए ठोस प्लान बनाने के निर्देश दिए

जयपुर। नगर निगम हेरिटेज आयुक्त डॉ निधि पटेल ने मंगलवार को निगम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान आयुक्त निधि पटेल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आमजन की समस्याओं का जल्द निस्तारण करें। इस दौरान निगम आयुक्त ने ऑनलाइन पोर्टल राजकाज पर पेंडिंग शिकायतों को लेकर प्रत्येक निगम अधिकारी से वन टू वन संवाद किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि ऑनलाइन पेंडेंसी को बग़ाय़ा नहीं जाएँ, अपितु नियत समय में ही समस्याओं का ठोस निस्तारण कर राहत प्रदान की जाएँ।

जोन उपायुक्त अपनी टीम के साथ करें समीक्षा बैठक :-

इस दौरान निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल ने कहा कि संपर्क पोर्टल या अन्य ऑनलाइन पोर्टल पर अधिकांश समस्याएं सीवर, सफाई व्यवस्था को लेकर ही आ रही है। ऐसे में हेरिटेज निगम के



हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि (बीच में) ने समीक्षा बैठक की ली।

सभी जोन उपायुक्त अपने अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक करें और इन समस्याओं का निस्तारण भी कराएं। जिससे कि आमजन को परेशान नहीं होना पड़े। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जिन जगहों पर सीवर या सफाई संबंधी समस्या ज्यादा आती हो, वहां पर निगम अधिकारी खुद

■ उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जिन जगहों पर सीवर या सफाई संबंधी समस्या ज्यादा आती हो, वहां पर निगम अधिकारी खुद मौके पर जाएँ और आमजन से संवाद कर समस्या का निदान कराएं

कि वे अपने अपने जोन में सड़क, सीवर और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं के निस्तारण के लिए ठोस प्लान बनाएं और इन कार्यों की ऑडिट भी कराएं। जिससे निर्माण कार्य समय पर कम बजट में गुणवत्ता पूर्ण पूरा हों सकें। इस दौरान समीक्षा बैठक में सभी जोन उपायुक्त, शाखा प्रभारी और इंजीनियरिंग विंग के अधिकारी मौजूद रहे।

कार्यशाला प्रतिभागियों की संयुक्त ध्रुवपद प्रस्तुति आज

जयपुर। जवाहर कला केन्द्र की ओर से आयोजित ध्रुवपद गायन प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन समारोह बुधवार 23 को आयोजित किया जाएगा। सायं 5 बजे सभी प्रतिभागी संयुक्त ध्रुवपद गायन की प्रस्तुति देंगे। 7 से जारी कार्यशाला में घरानेदारी के साथ कार्यशाला की विशेषज्ञ गुरु विदुषी प्रोफेसर डॉ मधु भट्ट तैलंग एवं उनके गुरु पद्म पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग द्वारा सृजित रचनाओं के नवाचार ख़ास होंगे।

भूले-बिसरे नगमों की महफिल में सजी सुरों की शाम

जयपुर। पांचजन्य संगीत फाउंडेशन समिति के तत्वावधान में मानसरोवर के होटल रुद्र विलास के सभागार में कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सालासर धाम से पधारं जय पुजारी ने किया कार्यक्रम में सुफी संगीत, गज़ल और पुराने नगमों की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। देश के सुप्रसिद्ध दिवंगत गायक रवीन्द्र जैन के शिष्य सुशील बावेजा (धनबाद) ने

तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज जैसे ही सुनाया माहौल राम मय हो गया और इंडियन आइडियल फेम अतुल राव ने जैसे ही मेहंदी इसन साहब की बहुत प्रसिद ग़ज़ल रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ,पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है ऐसी कई गज़लें सुनायीं सुन कर सभी संगीत प्रेमी मंत्र मुग्ध हो गये (जयपुर) ने अपने मधुर स्वरो से श्रोताओं को पुराने सौ की संगीत यात्रा पर ले चलने का कार्य

किया। सावन की भीगी भीगी रात में पुराने नगमों की स्वर लहरियों ने श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करने के साथ ही संगीत के अनगिनत प्रेमियों से मिलवा दिया।

कार्यक्रम का संचालन सुप्रसिद्ध भजन गायक निशा शर्मा किया। कार्यक्रम को और अधिक जीवंत बनाने के लिए वायलिन पर महावीर रावल, की-बोर्ड पर आकाश, गिटार पर रवि कुमार और तबले पर विनय राव ने संगत की।

गोविंद देव जी मंदिर में पार्थिव शिवलिंग पूजन के पोस्टर का विमोचन

जयपुर। हरियाली अमावस्या 24 जुलाई कनक घाटी स्थित गोविंद देव जी ठिकाने के काला महादेव मंदिर में पार्थिव शिवलिंग पूजन का आयोजन किया जाएगा।

■ कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रशांत शर्मा के आचार्यत्व में 21 वैदिक विद्वानों की टोली द्वारा किया जाएगा



महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सात्रिध्व में मंदिर के सेवाधिकारी मानस गोस्वामी ने आयोजन के पोस्टर का विमोचन किया।

कराया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रशांत शर्मा के आचार्यत्व में 21 वैदिक विद्वानों की टोली द्वारा किया जाएगा। आयोजन की व्यवस्थाओं में 20 स्वयंसेवकों की टीम तैनात रहेगी। कार्यक्रम सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा। विभिन्न तीर्थों के जल और दुग्ध मिश्रित जल से महाभिषेक किया जाएगा। इस दौरान रूद्री पाठ होंगे। फूलों से मनोरम श्रृंगार कर सामूहिक आरती की जाएगी।

जयपुर। चांदपोल बाजार व्यापार मंडल के तत्वावधान में शराब की दुकान खोलने को लेकर स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए।

चांदपोल व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया की इस दुकान के आसपास सात मंदिर स्थित हैं, जिनमें तीन बालाजी के मंदिर, तीन शिव जी के मंदिर, एक सनी मंदिर है। जहां पर स्थानीय लोग दूर-दूर से भगवान की पूजा करने व शनि महाराज को तेल चढ़ाने आते है। उनका कहना है कि इस दुकान के खुलने से क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस दुकान को खोलने की अनुमति न दी जाए। सुभाष गोयल ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस दुकान को खोलने की अनुमति न दे और क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान करे।महामंत्री घनश्याम भूतड़ा ने बताया कि इससे पूर्व भी इसी क्षेत्र में शराब की दुकान थी। जिसे बड़ी मुश्किलों से बंद कराया था। चांदपोल व्यापार मंडल गत 2 वर्ष से आबकारी विभाग ,कलेक्टर, और पुलिस प्रशासन

हैरिटेज सिटी कॉन्ट्रेक्टर्स सोसायटी ने ग्रेटर निगम कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन

- कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की उद्यान शाखा में हाल ही में हुए "वन टाइम प्लांटेशन" से संबंधित टेंडरों में अनियमितताओं की शिकायत मंगलवार को ग्रेटर निगम कमिश्नर डॉ. गौरव सैनी के पास पहुंची। हैरिटेज सिटी कॉन्ट्रेक्टर्स सोसायटी ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि, ग्रेटर निगम में 30 लाख रुपए से कम के टेंडरों में राजस्थान पारदर्शिता और सार्वजनिक खरीद अधिनियम (आरटीपीपी एक्ट) के नियमों के विपरीत मनमानी शर्तें जोड़ी गईं, जिनका उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति या फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाना प्रतीत होता है।



यूनियन अध्यक्ष रघुवीर शर्मा ने आयुक्त गौरव सैनी को ज्ञापन सौंपा ।

से बाहर होते दिख रहे है। उन्होंने बताया कि हाल ही में हैरिटेज नगर निगम ने भी टेंडर जारी किए हैं, परंतु वहां 30 लाख रुपए तक कोई शर्त नहीं लगाई गई। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने भी पूरी पारदर्शिता रखी। इससे ग्रेटर निगम की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। रघुवीर शर्मा ने कहा कि पूर्व में भी 16 जुलाई को इस संदर्भ में ज्ञापन

■ यूनियन अध्यक्ष रघुवीर शर्मा ने आयुक्त को शिकायत में बताया कि, उद्यान शाखा ने आरटीपीपी एक्ट के विपरीत मनमानी शर्तें जोड़ी, इससे फर्म विशेष को फायदा पहुंचाने की संभावना

■ 30 लाख से कम के टेंडर में जेडीए और हैरिटेज निगम में शर्तें नहीं, फिर ग्रेटर निगम में क्यों?

की टिप्पणी करके फाइलें लौटाई जा रहा है। ऐसे में यहां अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे है। तमाम शिकायतें सुनने के बाद आयुक्त गौरव सैनी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करवाने का आश्वासन दिया है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा कर जयपुर लौटे श्रद्धालु

जयपुर। पांच वर्षों के अंतराल के बाद गत 4 जुलाई को लिपुलेख मार्ग से प्रारंभ हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए राजस्थान के श्रद्धालु 22 दिन बाद मंगलवार को सुकशाल वापस जयपुर लौट आए। तीर्थयात्रियों का दल सोमवार रात दिल्ली पहुंचा, जहां गाजियाबाद स्थित कैलाश मानसरोवर सेंटर पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद सभी श्रद्धालु अपने-अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो गए। राजस्थान से यात्रा में सम्मिलित हुए वरिष्ठ राजेश नागपाल, नरेंद्र बैद और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एस संगंधि भी इस दल का हिस्सा थे। मंगलवार शाम को चांदी की टकसाल स्थित काले हनुमान जी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान

■ काले हनुमान-गोविंद देवजी के किए दर्शन

तीनों यात्रियों ने अपनी यात्रा का अनुभव साझा किया। जयपुर में परिजनों, श्रद्धालुओं एवं शुभचिंतकों ने सभी का माल्यार्पण कर आत्मीय स्वागत किया। यात्रियों ने बताया कि 21000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित कैलाश मानसरोवर की यह यात्रा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण रही। यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा डेरापुक से आरंभ हुआ, जहां 15000 फीट से चढ़कर 19500 फीट तक जाना पड़ा। संकरे और सीधी चढ़ाई वाले मार्ग में ऑक्सीजन की कमी का अनुभव हुआ। कई यात्रियों को

महिला की चेन तोड़ भागे बाइक सवार बदमाश

जयपुर। मानसरोवर थाना इलाके में दिनदहाड़े एक बाइक सवार बदमाश ने स्कूटी से जाती महिला के गले से सोने की चेन और पैडल तोड़ लिया। घटना थाने से महज कुछ दूरी पर हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। मानसरोवर थाना पुलिस के अनुसार कि चेन स्नेचिंग की वारदात प्रेणा जैन (35) निवासी मानसरोवर के साथ हुई है। जो सोमवार दोपहर अपनी छह वर्षीय बेटी को सेक्टर 5 स्थित प्राइवेट स्कूल से स्कूटी पर लेकर घर लौट रही थी। इस दौरान मानसरोवर के महिला थाना (साउथ) से पचास मीटर दूर पर पीछे से आए बाइक सवार एक बदमाश ने बाइक को स्कूटी के पास धीमा करते हुए उसके गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़ ली। इससे पहले महिला कुछ समझ बदमाश कुछ सेकेंड में ही आंखों से ओझल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश की जा रही है।

‘ मोदी सरकार के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान में तेजी से हो रहा विकास ’

जयपुर । ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अपार संभावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सतत रूप से कार्य कर रहा है। मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना, सूर्य मित्र योजना, वरुण मित्र योजना और जल ऊर्जा मित्र योजना के तहत ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में जून 2025 तक 59979 लाभान्वित परिवारों से 252 मेगावाट, गुजरात में 526694 लाभान्वित परिवारों से 1443 मेगावाट और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 26312 लाभान्वित परिवारों से 85 मेगावाट संयंत्र स्थापित किए जाने का समझौता हस्ताक्षरित किया गया। राज्यसभा संसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में नवीन

■ पीएम सूर्य घर योजना में राजस्थान, गुजरात और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 6 लाख 13 हजार लाभान्वित परिवारों से 1781 मेगावाट क्षमता के हुए समझौते : मदन राठौड़

एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने यह जानकारी सदन में दी। राज्यसभा संसद मदन राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी मुहैया करवाई जाती है। मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक राजस्थान, गुजरात और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पीएम

सूर्य घर योजना के लिए 1032 करोड़ तथा पीएम कुसुम योजना के तहत 293 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसमें राजस्थान को दोनों योजना के तहत 257 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। केंद्र सरकार के प्रयास से 30 जून तक राजस्थान में 37818 मेगावाट क्षमता, गुजरात में 37494 मेगावाट और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5048 मेगावाट के तवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसी तरह इन क्षेत्रों में 80361 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राज्यसभा संसद मदन राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से ऊर्जा क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण तक दिया जा रहा है। सूर्य मित्र योजना के तहत इन क्षेत्रों के 63713 व्यक्तियों को, वरुण मित्र योजना में 1276 और ऊर्जा मित्र कार्यक्रम में 601 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

मंदिर की दहलीज को प्रणाम कर दान पात्र चोरी कर ले गया बदमाश

जयपुर। हरमाडा थाना इलाके में एक मंदिर से दानपात्र चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में बदमाश मंदिर का गेट खोलकर अंदर घुसा। और फिर मंदिर की दहलीज को प्रणाम कर दान पात्र उठा चोरी कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

जांच अधिकारी एसएसआई प्रमोद कुमार ने बताया कि थाना इलाके के गोविन्दपुरा निवासी गोविंद शरण जांगिड़ ने मामला दर्ज करवाया है कि गोविन्दपुरा में खाखीजी महाराज का मंदिर है। जहां चोरों ने चोरी की नीयत से मंदिर को निशाना बनाते हुए मंदिर का गेट खोलकर बदमाश अंदर घुसे। मंदिर में रखे दानपात्र को चोरी कर ले गए। मंदिर पूजा करने आने पर दान पात्र गायब मिला। वहीं मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर चोर की करतूत कैद मिली। जहां मंदिर में एक बदमाश अंदर आया। गेट खोलकर अंदर घुसे बदमाश मंदिर में रखा दानपात्र उठाकर चोरी कर ले गया। मंदिर में चोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। चोरी गए दानपात्र में हजारों रुपए थे। पुलिस फुटेज में कैद हुए चोर की तलाश कर रही है।

विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या

जयपुर। वैशाली नगर थाना में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि विवाहिता तीन साल पहले उसने लव-मैरिज की थी। मृतका के परिवार की ओर से थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

सहायक पुलिस आयुक्त वैशाली नगर आलोक गौतम ने बताया कि बहरोड़ के कोटपूतली की रहने वाली भारती कंवर (25) ने फांसी का फंदा लगा कर आत्महत्या की है। तीन साल पहले भारती ने गांव के ही रहने वाले आकाश सिंह के साथ भागकर लव-मैरिज की थी। शादी के बाद से वैशाली नगर स्थित कोस्मो कॉलोनी में वह अपने पति आकाश के साथ रह रही थी। आकाश और भारती दोनों एक ग्राइवेट बैंक में नौकरी करने लगे। गत दिनों पहले पति के सोने के बाद कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आकाश ने जागने पर भारती को ढूंढा तो दूसरा कमरा अंदर से बंद मिला। काफी गेट खटखटाने के बाद भी कोई जबाब नहीं मिला। पड़ोसियों की मदद से धक्का देकर गेट खोलने पर कमरे में भारती फंदे से लटकती मिली।

■ विवाहिता तीन साल पहले उसने लव-मैरिज की थी,मृतका के परिवार की ओर से थाने में मामला दर्ज करवाया है

आत्महत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबूत जुटाने के बाद फंदे से शव को नीचे उतारा। पुलिस ने शव को कांवेरिया अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। इधर मृतक भारती की मां राजबाला ने दामाद आकाश सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया है कि आकाश सिंह नशे का आदी था। आए दिन वह भारती से मारपीट भी करता था। नशे में घर आकर आकाश के मारपीट और रुपये की मांग के बारे में भारती ने कई बार फोन कर बताया था। मृतका आत्महत्या ने से पहले भारती ने इमोशन स्टोरी इंस्टाग्राम पर लगाई थी।अगले दिन सुबह भारती की मौत की सूचना मिली थी। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शादी का झांसा देकर तीन साल तक एक युवती से देह शोषण

जयपुर। रामगंज थाना इलाके में शादी का झांसा देकर युवक ने तीन साल तक एक युवती से देह शोषण करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता ने आरोपित युवक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। पुलिस ने बताया कि राजा पार्क की रहने वाली युवती ने मामला दर्ज करवाया है कि कुछ साल पहले उसकी मुलाकात आरोपित से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपित ने उससे दोस्ती कर ली। मिलने-जुलने के दौरान आरोपित ने उसके सामने शादी करने का झांसा दिया। पीड़िता का आरोप है कि जुलाई-2022 में मिलने के बहाने उसे अपने यहां बुलाया। मिलने जाने पर आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की। विरोध करने पर शादी करने का वादा किया। शादी करने का झांसा देकर उसका देह शोषण करने लगा। पिछले करीब तीन साल तक आरोपी ने उसके साथ शादी का झांसा देकर देह शोषण किया। जून-2025 में शादी करने का दबाव बनाने पर आरोपित ने मना कर दिया। इसके बाद पीड़िता थाने पहुंची।

अति पिछड़ा वर्ग एवं गुर्जर समाज की विभिन्न मांगों पर चर्चा की

जयपुर । शासन सचिवालय में मंगलवार को अति पिछड़ा वर्ग एवं गुर्जर समाज की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए मंत्रीगण समिति की द्वितीय बैठक आयोजित की गयी। बैठक में संसदीय

■ बैठक में देवनारायण योजना की प्रगति, भर्तियों में आरक्षण, आन्दोलन प्रभावितों को अनुकम्पा नियुक्ति, 5 प्रतिशत अति पिछड़ा आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल कराने सहित समस्त बिन्दुओं की समीक्षा की

कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत तथा गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेदम ने भाग लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर बनी समिति की बैठक में देवनारायण योजना की प्रगति, रोस्टर



बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत तथा गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेदम ने भाग लिया।

एवं विभिन्न भर्तियों में आरक्षण, आन्दोलन प्रभावितों को अनुकम्पा नियुक्ति, 5 प्रतिशत अति पिछड़ा आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल कराने सहित समस्त बिन्दुओं की समीक्षा की गयी। समिति ने कार्मिक विभाग को सकारात्मक रूप से विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण करने के पर विचार किया गया। साथ ही गुर्जर आरक्षण समिति द्वारा पिछली बैठक में सुझाएं सातों बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आगामी बैठक में सभी बिंदुओं के फैन्चुअल रिपोर्ट मंगवाने और उन

पर चर्चा करने निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अपर्णा अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग भास्कर ए. सावंत, प्रमुख शासन सचिव चक्रित्सा गायत्री ए. राठौड़, शासन सचिव, कार्मिक विभाग डॉ. कृष्णा कान्त पाठक, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल, निदेशक न्याय एवं संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आशीष मोदी सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

